

प्रस्ताव पास कराने की तैयारी, पांच लाख को मिलेगा रोजगार

यूपी में 1000 ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर बनेंगे

तैयारी

■ अंजित खारे

लखनऊ। यूपी में 1000 ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर स्थापित होंगे। इसके जरिए पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्हें स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को जमीन से लेकर स्टांप ड्यूटी में छूट तक तमाम रियायतें दी जाएंगी। रियायतों का आधार रोजगार की संख्या, नियांत्रित वृद्धि व नवाचार होगा। यूपी सरकार के आईटी विभाग ने नई ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर नीति तैयार की है। इसे जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

निवेशकों को फ्रंट एंड लैंड सभिसडी के तहत गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 30 प्रतिशत पर, पश्चिमी यूपी (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद) व मध्य यूपी में 40 प्रतिशत पर व पूर्वांचल बुदेलखंड में 50 प्रतिशत के रेट पर जमीन दी जाएगी। अगर परियोजना समय से नहीं लगी तो लैंड पर इस सभिसडी की 12 प्रतिशत सालाना पर वसूली भी होगी। जमीन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट होगी। अधिकतम एक करोड़ तक का टर्म लोन लेने पर निवेशकों को पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सभिसडी दी जाएगी। लोज रेट,



- 24 घंटे हफ्ते में सातों दिन चलेंगे सेंटर
12 % सालाना दर पर वसूली मी होगी देरी होने पर

क्या है ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर वउनकी उपयोगिता



यह ऐसे बहुआयामी सुविधा युक्त सेंटर हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, डाटा विश्लेषक, साइबर सिक्योरिटी, व्हाउट - व्हांटम कम्यूटिंग, रोबोटिक्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आदि पर कंपनी को तकनीकी उपलब्ध कराते हैं। यह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अहम कड़ी होते हैं। यह हाईवैल्यू आपरेशंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिजिटल ट्रांसफार्मेशन पर काम करते हैं।

35000 हजार उच्च शिक्षित प्रशिक्षित पेशेवर



यूपी में इस समय 200 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफॉर्मिंग व आईटी कंपनियां हैं। जिसमें 35000 हजार उच्च शिक्षित प्रशिक्षित पेशेवर काम कर रहे हैं। यहां 40 आईटी पार्क, व 25 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र हैं। नोएडा इस वर्ष ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर का हवा है। लखनऊ आर्टिफिशियल इंटलीजेंस का हवा बनने जा रहा है।